



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2011/चैत्र 3, 1933

No. 65]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2011/CHAITRA 3, 1933

वित्त मंत्रालय

(आधिकार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2011

संख्या 18/1/2011- आरई : सरकार ने वर्ष 2010-11 के अपने बजट में, अन्य बातों के अलावा, वित्तीय क्षेत्रक कानूनों को मौजूदा अपेक्षाओं के समनुरूप बनाने के लिए उनका पुनर्लेखन करने तथा उनमें संशोधन करने के उद्देश्य से वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग का गठन करने की घोषणा की थी। तदनुसार वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्न शामिल होंगे :

(i) अध्यक्ष	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. एन. श्रीकृष्णा
(ii) सदस्य	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) देबी प्रसाद पाल
(iii) सदस्य	डा. पी. जे. नायक
(iv) सदस्य	श्रीमती के. जे. उदेशी
(v) सदस्य	श्री येज़दी एच. मालेगाम
(vi) सदस्य	प्रो. जयंत वर्मा
(vii) सदस्य	प्रो. एम. गोविंद राव
(viii) सदस्य	श्री सी. अच्युथन
(ix) सदस्य संयोजक	श्री धीरेंद्र स्वरूप
(x) सदस्य, नामिती	संयुक्त सचिव (पूंजी बाजार)

श्री सी. के. जी. नायर आयोग के सचिव होंगे।

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :-

- I. भारत में वित्तीय क्षेत्र को अभिशासित करने वाली विधायी और विनियामक प्रणाली की संरचना का अध्ययन करना, जिसमें निम्न शामिल हैं :-
 - क. वित्तीय क्षेत्रक को अभिशासित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, सेबी अधिनियम इरडा अधिनियम, पीएफआरडीए अधिनियम, एफसीआरए, एससीआरए, फेमा आदि सहित वर्तमान विधान की समीक्षा करना;
 - ख. आंतरिक संरचनाओं और बाह्य संरचनाओं (सरकारी विभाग और मंत्रालय) सहित ऐसे विधान के प्रशासन की आवश्यकतानुसार समीक्षा करना;
 - ग. विविध विनियामकों द्वारा गृहीत कार्यक्षेत्रों के परस्पर निष्पादन की समीक्षा करना;
 - घ. प्रत्येक विनियामक के अंतर्गत विभागों के कार्यक्षेत्रों की समीक्षा करना; और वियोजन/संयोजन, और ऐसे अन्य सुप्रवाहीकरण की जरूरत पर विचार करना;
 - ङ. बाजार में विनियामकों के हित संघर्ष संबंधी मसलों की समीक्षा करना;
 - च. अधीनस्थ विधान के प्रारूपण और कार्यान्वयन के तरीके की समीक्षा करना;
 - छ. विनियामक प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों के पात्रता मानदंडों की, और उनके कार्यकाल, पदधारण से जुड़े मुद्दों की तथा प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा सीखे सबकों के उपयोग और प्रतिधारण के उपायों की समीक्षा करना;
 - ज. वित्त क्षेत्रक विधान के उपयोगकर्ताओं संबंधी तमाम मामलों पर एक संयोजित अपीलीय निरीक्षण का विश्लेषण करना;
- II. यह जांच करना कि क्या किसी विधान में अधीनस्थ विधान के प्रत्येक अंश में निहित विधायी आशय वाला सैद्धांतिक विवरण रहना ही चाहिए ताकि विधान का सोद्देश्य आशय कानून के उपयोगकर्ताओं और न्यायालयों के लिए स्पष्ट और पारदर्शक हो जाए।
- III. यह जांच करना कि क्या अधीनस्थ विधान के प्रारूप के लिए सार्वजनिक प्रतिसूचना आपाती कार्रवाईयों को छोड़कर अनिवार्य बनाई जानी चाहिए।
- IV. जब नियामक कार्रवाई एकपक्षीय आधार पर की जाएगी, आपातकालीन शक्तियों को लागू करने के पैरामीटरों की जांच करना;
- V. वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत अन्य विनियामक तंत्रों में फेमा और एफडीआई नीतियों के तहत मुद्रा नियंत्रणों के परस्पर प्रभाव का अध्ययन करना;
- VI. विनियामकों पर और सरकार से उनकी स्वायत्तता पर निगरानी के समुचित उपायों की जांच करना;
- VII. वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के बाद के विगत दो दशकों में न्यायिक फैसलों और नीतिगत बदलावों के आधार पर किसी पुराने विधान के अविलंब निरसन और कानून के पुनर्निरूपण की जरूरत की जांच करना;

- VIII. भारतीय बाजार में वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ता की डाटा गोपनीयता और सुरक्षा के मसलों की जांच करना;
- IX. भारत में वित्तीय सेवाओं के प्रदाय और उनकी प्रभावोत्पादकता में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका संबंधी विधान की जांच करना;
- X. सरकार द्वारा तथा विनियामकों द्वारा गठित विविध विशेषज्ञ समितियों द्वारा पहले से ही गई सभी सिफारिशों की जांच करना तथा आसानी से स्वीकृत हो सकने वाले उपायों पर अमल करना;
- XI. भारत में अंतरराज्यीय वित्तीय सेवाओं की अवसंरचना में सुचारु कार्य सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों और विधानमंडलों की भूमिका की जांच करना;
- XII. किन्हीं अन्य संबंधित मामलों की जांच करना।
3. आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रियाविधि तैयार करेगा तथा वह परामर्शदाताओं, सलाहकारों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है तथा जिस प्रयोजनार्थ आयोग का गठन किया गया है, उस प्रयोजन के लिए संगत क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठ तथा विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं को अनुसंधान कार्य का बहिस्तोषण कर सकता है। वह यथावश्यक समझी जाने वाली सूचना मंगवा सकता है तथा साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। भारत सरकार के मंत्रालय तथा विभाग ऐसी सूचना तथा दस्तावेज एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे जो आयोग द्वारा अपेक्षित हो। भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें तथा सभी अन्य संबंधित आयोग को अपना पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।
4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।
5. आयोग अपनी अनुशंसाएं इस राजपत्रित अधिसूचना की तिथि से 24 माह के भीतर करेगा। जब और जैसे अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया जाता है, आयोग आवश्यकता होने पर किसी भी मामले पर रिपोर्टें भेजने पर विचार कर सकता है।

आर. गोपालन, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th March, 2011

No. 18/1/2011-RE.—The Government in its Budget 2010-11 had, inter alia, announced the setting up of a Financial Sector Legislative Refórms Commission (FSI.RC) with a view to rewriting and cleaning up the financial sector laws to bring them in tune with current requirements. Accordingly, it has been decided to constitute the Financial Sector Legislative Reforms Commission comprising of the following:

i)	Chairman	Justice (Retd.) B.N.Srikrishna
ii)	Member	Justice (Retd.) Debi Prasad Pal
iii)	Member	Dr. P.J. Nayak
iv)	Member	Smt. K.J. Udeshi
v)	Member	Shri Yezdi H.Malegam
vi)	Member	Prof. Jayant Varma
vii)	Member	Prof. M. Govinda Rao
viii)	Member	Shri C. Achuthan
ix)	Member Convenor	Shri Dharendra Swarup
x)	Member, Nominee	Joint Secretary (Capital Markets)

Shri C.K.G. Nair will be the Secretary to the Commission

2. The Terms of Reference of the Commission will be as follows:-

I. Examining the architecture of the legislative and regulatory system governing the financial sector in India, including:

- a. Review of existing legislation including the RBI Act, the SEBI Act, the IRDA Act, the PFRDA Act, FCRA, SCRA, FEMA etc., which govern the financial sector;
- b. Review of administration of such legislation, including internal structures and external structures (departments and ministries of government), if required;
- c. Review of inter-play of jurisdictions occupied by various regulators;
- d. Review of jurisdiction of departments within each regulator, and consider need for segregation / combination, and such other streamlining;
- e. Review of issues relating to conflict of interest of regulators in the market;
- f. Review of the manner in which subordinate legislation is drafted and implemented;

g. Review of eligibility criteria for senior officers in regulatory authorities and issues relating to tenure, continuity, and means of tapping and retaining lessons learnt by each authority.

h. Examine a combined appellate oversight over all issues concerning users of financial sector legislation.

II. Examine if legislation should mandate statement of principles of legislative intent behind every piece of subordinate legislation in order to make the purposive intent of the legislation clear and transparent to users of the law and to the courts.

III. Examine if public feedback for draft subordinate legislation should be made mandatory, with exception for emergency measures.

IV. Examine prescription of parameters for invocation of emergency powers where regulatory action may be taken on an *ex parte* basis.

V. Examine the interplay of exchange controls under FEMA and FDI Policy with other regulatory regimes within the financial sector.

VI. Examine the most appropriate means of oversight over regulators and their autonomy from government.

VII. Examine the need for re-statement of the law and immediate repeal of any out-dated legislation on the basis of judicial decisions and policy shifts in the last two decades of the financial sector post-liberalisation.

VIII. Examination of issues of data privacy and protection of consumer of financial services in the Indian market.

IX. Examination of legislation relating to the role of information technology in the delivery of financial services in India, and their effectiveness.

X. Examination of all recommendations already made by various expert committees set up by the government and by regulators and to implement measures that can be easily accepted.

XI. Examine the role of state governments and legislatures in ensuring a smooth inter-state financial services infrastructure in India.

XII. Examination of any other related issues.

3. The Commission will device its own procedure and may appoint consultants, advisors and experts and outsource research work to institutions of repute and expertise in the relevant area for the purpose for which the Commission has been set up. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trusts that State Governments and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.
4. The Commission will have its headquarters in Delhi.
5. The Commission will make its recommendations within 24 months of the date of this Gazette Notification. It may consider, if necessary, sending reports on any of the matters as and when the recommendations are finalised.

R. GOPALAN, Secy.,